भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1690

10 फरवरी 2026 को उत्तरार्थ

विषय: बाढ़ से प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति

1690. श्री नारायण तातू राणेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में हाल ही में आई बाढ़ के कारण किसानों की फसलों और कृषि संपत्तियों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का राष्ट्रीय आपदा राहत कोष या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस संबंध में विशेष क्षतिपूर्ति देने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार की भविष्य में किसानों को ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए कोई स्थायी नीति बनाने की योजना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं के कारण जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध निधियों से प्राकृतिक आपदाओं के अनुरूप राहत उपाय करती हैं। 'गंभीर प्रकृति' की प्राकृतिक आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से एसडीआरएफ के अलावा, अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है और राज्य सरकार से प्राप्त ज्ञापन के आधार पर स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार इसे अनुमोदित किया जाता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदत्त की जाने वाली वित्तीय सहायता मुआवजे के रूप में नही होकर राहत के रूप में होती है।

राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त हो जाने पर, एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) का गठन किया जाता है और उसे मौजूदा मदों और मानदंडों के अनुसार क्षति का मौके पर आकलन करने और राहत कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि का आकलन करने के लिए भेजा जाता है। आईएमसीटी की रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय के सचिव/कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति (एससी-एनईसी) द्वारा विचार किया जाता है। तत्पश्चात, गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी), जिसमें वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष शामिल होते हैं, एससी-एनईसी की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करती है। एचएलसी एनडीआरएफ से राज्य को उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त सहायता की राशि को मंजूरी देती है, जो राज्य के एसडीआरएफ में उपलब्ध शेष राशि के समायोजन के अधीन होती है।

महाराष्ट्र राज्य को एसडीआरएफ के तहत वर्ष 2025-26 के दौरान 4176.80 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 3132.80 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 1044.00 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं। जिसमें से केंद्रीय हिस्से की दोनों किस्तें, प्रत्येक 1566.40 करोड़ रुपये, राज्य को जारी की जा चुकी हैं।

वर्ष 2025 की बाढ़ के कारण, क्षति का मौके पर आकलन करने के लिए राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने हेतु दिनांक 16.10.2025 को एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) का गठन किया गया था। आईएमसीटी ने दिनांक 03.11.2025 से 05.11.2025 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आईएमसीटी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जून से सितंबर 2025 की अवधि के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ के कारण कुल 98.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ, जिससे 34 जिलों के 120.83 लाख किसान प्रभावित हुए। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया और प्रभावित किसानों के लिए राहत और मुआवजे के रूप में 9700.87 करोड़ रुपये अनुमोदित किए। इसके अतिरिक्त, रबी सीजन के लिए बीज और अन्य संबंधित कृषि सामग्री के लिए प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये की सहायता राशि, अधिकतम 3 हेक्टेयर तक प्रदान की गई है। इस प्रयोजनार्थ, कुल 9611.17 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

सरकार ने खरीफ 2016 से उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से फसल क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और किसानों की आय को स्थिर करना है। इस योजना के तहत बुआई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक की क्षति के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है।

देश भर के किसानों से बहुत कम प्रीमियम लिया जाता है, जो खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 5% है। शेष बीमा प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से) को छोड़कर साझा किया जाता है जहां यह 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक (31.12.2025 की स्थिति के अनुसार) पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत भुगतान किए गए दावों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	**भुगतान किए गए दावे (रुपये करोड़ में)**				
	2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
महाराष्ट्र	1,323.5	4,708.8	5,419.3	9,586.4	5,774.8

*****